

Shri Hukam Chand
Kachhavaiya;
Shri A. N. Vidyalankar;

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether a proposal for the conversion of Provident Fund into a pension scheme for the Central Government employees is under consideration; and

(b) if so, the decision taken in the matter?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) and (b). No, Sir. However Government have under consideration a proposal to set up a Family Pension Fund for workers who are members of the Employees' Provident Fund and Coal Mines Provident Fund.

मूर राजकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए
 सरकारी क्वार्टर

279. श्री हुकम चन्द कल्पायः
श्री बड़े :

क्या निर्माण आवास तथा नगरीय विकास बंदी यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ऐसे कुछ नियम बनाये हैं जिन में सरकारी कर्मचारियों का मृत्यु के बाद उनके बच्चों को वार्षिक परांपरा होने तक सरकारी क्वार्टरों में रहने दिया जाय;

(ख) यदि हाँ, तो उसका व्योरा क्या है; और

(ग) उनसे किराया किस प्राधार पर बसूल किया जाता है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास बंदी (श्री बेहर चन्द जीना) : (क) से (ग). प्रावंटन नियमावली के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि प्रावंटों की मृत्यु के बाद उसका परिवार वास को उस किराये की अदायगत पर जो कि

प्रधिकारी अपनी मृत्यु से ठीक पूर्व घटा कर रहा था, चार महीने तक अपने पास रख सकता है। फिर भी, बच्चे की अन्तिम परीका प्रथवा परिवार में गंभीर बीमारी जैसे विशेष कारणों के आधार पर इस प्रवधि के बाद कुछ महीनों तक वह परिवार वास को अपने पास रख सकता है। बृद्धि की ठीक प्रवधि प्रत्येक मामले के प्रौद्योगिक्य पर निर्भर करती है, किन्तु प्रधिकारी अवधि छः महीने की है। बृद्धि की प्रवधि का किराया मूल नियम 45-ए के अन्तर्गत मानक किराये से दुगने दर पर प्रथवा मूल नियम 45-ए के अन्तर्गत पूल्ड मानक किराये से दुगना, इन दोनों में जो भी प्रधिक हो, बसूल किया जाता है।

बोधियों के लिए इवार्टर

281. श्री हुकम चन्द कल्पायः
श्री बड़े :

श्री पुढ़वीर सिंह :

श्रीमती सावित्री निगम :

श्री विश्वनाथ नाथ पाण्डेय :

श्री शिवचरण गुप्त :

क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रा 2 दिसंबर, 1965 के इताराकित प्रश्न में उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में श्रोतियों को रिहायशी मकान तथा अन्य श्रोतियों देने के सम्बन्ध में नियुक्त की गयी अनिवार्यता दियारियों को सरकार ने लान् कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) मकानों तथा श्रोतों जाटों का कितना किराया बसूल किया जायेगा; और

(घ) दिल्ली तथा नई दिल्ली में इस समय कितने श्रोतों हैं?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास बंदी (श्री बेहर चन्द जीना) : (क) और